

# मेडिकल काउंसिल में भ्रष्टाचार चरम पर

## व्यावसायिक शिक्षा के दूसरे क्षेत्र भी पीछे नहीं

**कें** द्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. केतन देसाई के रिश्तखोरी करते रंगे हाथों पकड़े जाने पर और उसके द्वारा किये गये अन्य भ्रष्टाचार के संदर्भ में बोल रहे थे।

डॉ. केतन देसाई को गिरफ्तार हुए एक माह से ज्यादा हो चुका है और आजाद साहब का बयान अब आ रहा है, इससे ही समझा जा सकता है कि वे इस मामले में कितने गंभीर हैं। मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अन्य मामलों का नियमन करने वाली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इस देश की इस सबसे बड़ी संस्था है। उसका ही अध्यक्ष दो करोड़ रुपये की रिश्त लेते हुए पकड़ा जाये, इससे भी शर्मनाक बात भला और क्या हो सकती है? यही नहीं, उसके पास भ्रष्टाचार से कमाया गया न जाने कितना धन है, इसका हिसाब अभी तक जांच एजेंसियों को नहीं मिल पाया है। हां, उसके पास से डेढ़ टन सोना अवश्य मिला है जो यह दिखाने के लिए काफी है कि इस व्यक्ति का भ्रष्टाचार का स्तर कितना ऊंचा है। दो करोड़ रुपये की रिश्त वह पंजाब के किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिये जाने के लिए ले रहा था।

जब से देश में शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण की शुरुआत हुई है, देश में प्राइवेट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज धड़ाधड़ खुलते जा रहे हैं। ये विश्व स्तर की शिक्षा प्रदान करने का दावा करके छात्रों का जम कर लूट रहे हैं। इनका स्तर बेहद गिरा हुआ होता है, पर एक बार जब सरकारी नियामक संस्थाओं से इन्हें मान्यता मिल जाती है तो इन्हें खुली लूट का लाइसेंस प्राप्त हो जाता है। समझा जा

### देसाई को सजा दिलाने में हील-हवाला

करोड़ों की रिश्तखोरी के मामले में रंगे हाथ पकड़े जाने पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. केतन देसाई के गिरफ्तार किये जाने पर सरकार अभी भी इंडियन पेनल कोड के तहत उसके द्वारा किये गये अपराधों पर मुकदमा नहीं चलाना चाहती है। देसाई के खिलाफ कार्रवाई के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इस संबंध में विधि मंत्रालय से राय मांगी गई है कि उसके खिलाफ कया कार्रवाई की जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि हमारे देश में सजा का प्रावधान छोटे अपराधियों के लिए ही है। मामूली चोरों और जेबकतरों को तो सजा आनन-फानन में दे दी जाती है, पर जहां देसाई जैसे बड़े डकैतों का सवाल आता है, सरकार विधि मंत्रालय से परामर्श चाहती है। क्या इंडियन पेनल कोड में देसाई जैसे अपराधियों के लिए सजा का उचित प्रावधान नहीं है? है क्यों नहीं। पर भूलना नहीं होगा कि देसाई जैसे उच्च पदस्थ लोग अकेले अपने दम पर अपराध नहीं करते, इनके अपराधों में तो सीधे-सीधे राजनेता यानी मंत्री आदि भागीदार होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को सजा दिलवाने में कई तरह के हील-हवाले किये जाते हैं और पूरी कोशिश तो यही की जाती है कि किसी भी तरह से ऐसे लोगों को सजा न भुगतनी पड़े। जहां तक ऐसे लोगों के लिए जेल का सवाल है तो आज सभी जानते हैं कि जेल में इनकी आरामतलबी के लिए किस तरह से सभी प्रबंध किये जाते हैं और जेल इनके लिए जेल न हो कर ससुराल की मानिन्द होती है।

सकता है कि इस तरह की संस्थाओं से पढ़े लिखे छात्र-छात्राएँ अपने पेशे में कितने दक्ष होते होंगे। यह कोई नई बात नहीं है कि डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन के दौरान कभी मरीजों के पेट में कैंचो तो कभी तौलिया छोड़ देने की घटनाएँ सामने आती रही हैं।

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को देश में उन छात्रों की डिग्री को भी मान्यता देने का अधिकार है जो विदेशों से शिक्षा प्राप्त कर के आते हैं। जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ है, वहां स्वतंत्र हुए देशों में मेडिकल की अधिकचरी शिक्षा देने वाली दुकानें खूब खुल गई हैं। काफी संख्या में पैसे वाले भारतीय छात्र वहां जा कर शिक्षा हासिल भी कर रहे हैं और वापस लौट कर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, पर उनकी शिक्षा की गुणवत्ता संदिग्ध है। लेकिन ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पैसा खर्च कर आसानी से अपने लिए मान्यता ले लेते हैं। मेडिकल की अधिकचरी शिक्षा देने वाली

दुकानें चीन में भी काफी फल-फूल रही हैं और वहां भी भारतीय छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। उनकी डिग्रियों की असलियत भी संदिग्ध है, पर काउंसिल में पैसा देकर कोई भी काम करा लेना काफी आसान है। यही कारण है कि जैसी-तैसी मेडिकल शिक्षा लेकर आये छात्रों-छात्राओं को इस देश की बीमार जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने और लूटने का मौका मिल जाता है।

गौरतलब है कि मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में चला आ रहा यह गोरखधंधा कोई आज का और नया नहीं है। डॉ. केतन देसाई ने कोई एक दिन में लूट का यह सारा माल नहीं बटोरा। उसकी लुटेरी गतिविधियां न जाने कब से जारी थीं। यही नहीं, जिस संस्था का अध्यक्ष ही इतना बड़ा लुटेरा हो, वहां और लोग कैसे होंगे, इसे भी समझना कठिन नहीं है। पर और किसी के खिलाफ जांच-पड़ताल की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। होना तो यह

चाहिए था कि पूरी संस्था के ही काम-काज की जांच-पड़ताल करनी चाहिए थी। पर जहां भ्रष्टाचार सत्ताधारियों की रग-रग में खून की तरह बह रहा हो, वहां जांच एजेंसियां कितना निष्पक्ष जांच करती हैं, इस पर भी आम जनता को संदेह है। रहा सवाल डॉ. केतन देसाई का तो उसके गिरफ्तार में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेडिकल काउंसिल के दूसरे पदाधिकारी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। एक व्यक्ति बेईमान और भ्रष्ट हो और बाकी सभी ईमानदार तो उसकी बेईमानी और लूट एक दिन भी नहीं चल सकती। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री को इन सारे मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए। लेकिन विचार करके वे करेंगे भी क्या, क्या सरकार में इतनी क्षमता है कि वह लूट और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पा सके। यहां सोचने वाल बात यह भी है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई भी इतने बड़े पैमाने पर लूट नहीं मचा सकता। इसलिए तय है कि डॉ. केतन देसाई की लूट में राजनेताओं का हिस्सा भी निश्चित तौर पर रहा होगा। इसकी जांच कौन करेगा?

उपलब्ध जानकारियों के अनुसार केतन देसाई पिछले दसियों बरस से करीब सात सौ करोड़ रुपया वार्षिक के हिसाब से लूटता आ रहा था। इसके भ्रष्टाचार का एक मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचा, उसने देसाई को पद मुक्त ही कर दिया था, लेकिन जल्द ही वह पुनः 'चुनाव' जीत कर फिर से अपने पर तैनात हो गया। यह न्यायिक व्यवस्था का एक लचर रवैया ही है जो केतन देसाई जैसे डकैत को जेल भेजने के बजाय केवल अस्थाई तौर पर पदमुक्त कर दिया। प्रश्न यह भी पैदा होता है कि क्या देसाई की लूट स्वास्थ्य मंत्री एवं सरकार को नज़र नहीं आ रही थी? यह किससे छिपा है कि तमाम मेडिकल कॉलेजों द्वारा खुली लूट मचाई जा रही थी, इसके बावजूद सरकार का उदासीन रवैया स्वतः सिद्ध करता है कि उक्त लूट

में इसके मंत्रियों की भी बराबर की हिस्सेदारी रही है। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो अथवा भाजपा की, वर्षों से चली आ रही इस लूट में सभी बराबर के हिस्सेदार रहे हैं। अपना हिस्सा डकार चुकने एवं देसाई को बलि का बकरा बनाने के बाद आज गुलाम नबी आजाद को यह भ्रष्टाचार इस कदर 'चुभ' रहा है वे इसको और बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वे कुछ नहीं करेंगे। कोई नया देसाई पकड़ कर लाया जायेगा और इसी बेपर्दा हो चुकी लूट को पर्दादारी में चलाया जाता रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में यह नाकाबिले बर्दाश्त लूट केवल मेडिकल तक ही सीमित नहीं है, राजनीतिज्ञों के आशीर्वाद से शिक्षा के हर क्षेत्र में यह पूरी तरह अपनी जड़ें जमा चुकी है। इससे पूर्व इंजीनियरिंग कॉलेजों को मान्यता देने वाली देश की उच्चतम संस्था एआईसीटीई के चेयरमैन यादव व उसके साथियों को भी इसी तरह पकड़ा गया था। उसे इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि वह लूट मचा रहा था, बल्कि वह इसलिए पकड़ा गया था कि वह पूर्व शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह का बेटाया हुआ था। जाहिर है, सत्ता परिवर्तन के बाद लूट का मौका किसी अन्य को भी तो दिया जाना चाहिए, तभी तो 'समाजवादी' समाज की स्थापना हो पायेगी। कुकुरमतों की तरह देश भर में खुलते जा रहे विश्वविद्यालय भी आम जनता को लूटने और बेवकूफ बनाने में किसी तरह भी पीछे नहीं रह गये हैं। इनकी स्वीकृति प्रदान करने वाले संस्थान एवं अधिकारी भी किसी देसाई अथवा यादव से पीछे नहीं हैं। दुकान रूपी इन अवैध विश्वविद्यालयों की तो बात छोड़िये, अब तो देश के सरकारी विश्वविद्यालय भी छात्रों को लूटने में किसी तरह भी पीछे नहीं रहना चाहते। इन्होंने ऐसे-ऐसे पाठ्यक्रम चला दिये हैं जिन पर ये विश्वविद्यालय बिना कुछ खर्च किये केवल डिग्रियां बेच कर अंधा मुनाफा काट रही हैं।

- प्रतिनिधि

# क्या होगा अब 'ग्रामीण चिकित्सा शिक्षा' का?

**रि**श्त लेते हुए गिरफ्तार कर लिए जाने के पूर्व डॉ. केतन देसाई और स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने मिल-जुल कर सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किये जाने के लिए डॉक्टरों के लिए एक विशेष तीन वर्षीय शिक्षा व्यवस्था की योजना बना कर अरबों रुपयों कमाने का जुगाड़ बना लिया था। पर केतन देसाई की गिरफ्तारी के बाद यह योजना फ़िलहाल खटाई में पड़ गई है। यह योजना ग्रामीण विशेष चिकित्सा शिक्षा के नाम पर संस्थान खड़े करने और छात्र-छात्राओं की भर्ती कर बेहिसाब पैसे कमाने की योजना थी। भारत एक ऐसा देश है जहां आजादी के 62 वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का कोई ढांचा अब तक खड़ा नहीं हो पाया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रत्येक 20,000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 27,000 लोगों पर मात्र एक चिकित्सक उपलब्ध है। गांवों में प्रशिक्षित चिकित्सक सिर से नहीं हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा अभी भी झोलाछाप डॉक्टरों के हवाले है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण चिकित्सा सेवा के नाम पर तीन वर्षीय चिकित्सा पाठ्यक्रम के औचित्य को साबित करना कठिन नहीं होता। लेकिन

सवाल है कि मेडिकल की जो डिग्री छः साल पढ़ाई और इंटरशिप के बाद मिलती है, वह तीन साल में ही कैसे दी जाती? क्या ग्रामीण किसी अन्य प्रजाति के जीव हैं जिनकी चिकित्सा के लिए अलग तरीकों की जरूरत पड़ेगी? क्या वे मनुष्य नहीं हैं? यहां तो जानवरों की चिकित्सा के लिए जो शिक्षा दी जाती है, वह भी तीन वर्षों में पूरी नहीं होती। फिर क्या ग्रामीण जानवरों से भी गये-बीते हैं? आखिर किस आधार पर स्वास्थ्य मंत्री ने इस विचार को स्वीकार किया कि ग्रामीणों की चिकित्सा के लिए शिक्षा दिये जाने का काम तीन वर्षों में ही पूरा किया जा सकता है?

बहरहाल, ग्रामीण चिकित्सा शिक्षा के लिए तीन वर्षों में ही डॉक्टर तैयार करना एक तरह से अंधों के बीच काना राजा की कहावत को चरितार्थ करने वाली बात थी। इससे समझा जा सकता है कि सरकार का ग्रामीणों के प्रति नज़रिया कैसा है?

आज कहने के लिए भी चंद विकसित गांवों में जो स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, वहां डॉक्टर तो क्या, नर्स तक भी नहीं आतीं। अधिकांश स्वास्थ्य केंद्र खंडरहाल हैं और वहां आसपास पशु चरते दिखाई पड़ते हैं। कभी-कभार भूले-भटके कोई नर्स आ गई तो वह मुफ्त की दवाइयां बीमार ग्रामीणों को बेच आती हैं और अगर कोई

**सवाल है कि मेडिकल की जो डिग्री छः साल पढ़ाई और इंटरशिप के बाद मिलती है, वह तीन साल में ही कैसे दी जाती? क्या ग्रामीण किसी अन्य प्रजाति के जीव हैं जिनकी चिकित्सा के लिए अलग तरीकों की जरूरत पड़ेगी? क्या वे मनुष्य नहीं हैं? यहां तो जानवरों की चिकित्सा के लिए जो शिक्षा दी जाती है, वह भी तीन वर्षों में पूरी नहीं होती। फिर क्या ग्रामीण जानवरों से भी गये-बीते हैं? आखिर किस आधार पर स्वास्थ्य मंत्री ने इस विचार को स्वीकार किया कि ग्रामीणों की चिकित्सा के लिए शिक्षा दिये जाने का काम तीन वर्षों में ही पूरा किया जा सकता है?**

मरीज ज्यादा ही बढहाल हुआ तो उसे कहीं भर्ती कराने के लिए दलाली करने लगती हैं।

गांवों में कोई व्यक्ति जो इस बात की जानकारी हासिल कर लेता है कि सिरदर्द, पेटदर्द, बुखार आदि की दवायें कौन-सी हैं, वही स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका निभाने लगता है। वह बीमार ग्रामीणों को दवायें बेच कर अपनी बेरोजगारी दूर करता है अथवा अपने लिए अतिरिक्त आमदनी का जुगाड़ करता है। इन दवाओं के गलत इस्तेमाल से कभी-कभी रियैक्शन होने के कारण बीमार व्यक्ति मौत के मुंह में भी

चला जाता है। सरकार ने इनकी 'भलाई' के लिए विशेष चिकित्सा शिक्षा योजना शुरू करनी चाही थी तो बुरा क्या किया था, कई लोग यह सवाल भी उठाते हैं। पर वे यह भूल जाते हैं कि मध्यमवर्गीय परिवारों के जो छात्र काफी धन खर्च कर इन विशेष चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में शिक्षा हासिल करते, वे क्या गांवों में रह कर मरीजों को चिकित्सा सेवा मुहैया कराते?

हर्गिज नहीं। वे गांवों में रहने कभी नहीं जाते। अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाये तो देश के अधिकांश गांवों में ढांचागत सुविधाओं का पूरा अभाव है। वे

गांव गिनती के ही होंगे जो अभी भी सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं। वहां न शिक्षा की व्यवस्था है और न ही अन्य किस्म की कोई सुविधा। ऐसे में यह सोचना खामखाली ही होगी कि कोई भी मध्यवर्गीय व्यक्ति जो किसी भी तरह की तकनीकी शिक्षा प्राप्त है, गांवों में जा कर रह सकता है। गांवों में जिन डॉक्टरों को नियुक्त करने के बारे में सोचा जा रहा है, भले ही वे आधी-अधूरी शिक्षा प्राप्त हों, रहेंगे तो शहरों में ही, भले ही इसके लिए इन्हें अपने ऊपर बैठे अधिकारियों को रिश्त देनी पड़े।

बहरहाल, अभी तो यह योजना खटाई में पड़ गई है, पर इसे किसी न किसी रूप में अवश्य शुरू किया जायेगा। ऐसी शिक्षा देने के लिए सरकार तो अपने संस्थान खोलने से रही, इस क्षेत्र में प्राइवेट धंधेबाज सामने आयेंगे और वे मनमानी फ्रीस लेकर मंत्रियों और अफसरों को भारी रिश्त दे कर अपना धंधा चलायेंगे। जिस दिन भी तीन वर्षीय मेडिकल डिग्री देने वाले शिक्षा संस्थान खोले जायेंगे, उपरोक्त खेल ही होगा। तीन वर्षीय डिग्री कोर्स की अवधारणा ही सिर से गलत है। इसमें यह नीयत छिपी हुई है कि ग्रामीण तो ढोर-डांगर हैं।

- मनोज